

समक्ष माननीय अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल म.प्र.

ग्वालियर केम्प, भोपाल म.प्र.

120

भोपाल
जिगरानी-6119/2018/अनावेदक/अनुवेदक

प्रकरण निगरानी क्र. पी.बी.आर...../15
हरिप्रसाद राठौर आ. स्व. श्री सुन्दरलाल



आयु लगभग 85 वर्ष,
निवासी-ग्राम भौरी, तहसील हुजूर
जिला भोपाल (म.प्र.)
..... आवेदक/निगरानीकर्ता
विरुद्ध

श्रीमती गीता राजानी
पति श्री नरेश राजानी, आयु वयस्क
निवासी-27, रीवेरा टाउन, फेस टी.टी.नगर
तहसील हुजूर जिला भोपाल
.....रेस्पॉडेंट/अनुवेदक

निगरानी याचिका अर्न्तगत धारा 50 म.प्र.भू रा.संहिता 1959

अभिभावक श्री.....
द्वारा आज दिनांक 19/11/18
को पेश।

विद्यमान राजस्व मापदण्ड

माननीय महोदय,
आवेदक/निगरानीकर्ता

अधीनस्थ न्यायालय

तहसीलदार हुजूर जिला भोपाल के अधीनस्थ राजस्व
तहसीलदार, तहसील हुजूर जिला भोपाल के अधीनस्थ
राजस्व निरीक्षक मण्डल वृत्त-4, तहसील हुजूर जिला
भोपाल के सीमांकन प्रकरण क्रमांक 48/अ-12/2017-18
मे आदेश दिनांक 02/01/2018 से असंतुष्ट एवं दुखी होकर
यह निगरानी आदेश से असंतुष्ट एवं दुखी होकर यह
निगरानी आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त नहीं होन से
प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने की रसीद के आधार पर
माननीय महोदया के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है:-

प्रकरण के तथ्य:-

अ. यह कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि
अनावेदिका द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसील हुजूर जिला

निरंतर.....2

2520
19/11/18
25/11/18

हरिप्रसाद राठौर

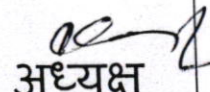
(Handwritten signature)

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 6119/2018/भोपाल/भूरा

जिला भोपाल

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-10-18	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री विदयराज मालवीय द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 2-1-18 के विरुद्ध इस न्यायालय में लगभग 8 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । आवेदक पक्ष द्वारा निगरानी प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब कारण आदेश की जानकारी नहीं होना एवं आवेदक के बीमार होने का कारण बताया गया है परन्तु तर्क के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं इसलिये आवेदक द्वारा बताया गया विलम्ब का कारण समाधानकारक मान्य नहीं किया जा सकता है । इस संबंध में 1992 आरएन 289 लंगरी(श्रीमती) तथा अन्य विरुद्ध छोटा तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:-</p> <p>"धारा - 5 - व्याप्ति - अधिकारिता की प्रकृति - वैवेकिक है - पक्षकार विलम्ब माफी के लिये अधिकार के रूप में हकदार नहीं है - पर्याप्त कारण का सबूत - अधिनियम की धारा 5 द्वारा न्यायालय में निहित अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये पुरोभाव्य शर्त है - न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति के अधीन अधिनियम अथवा विधि द्वारा विहित परिसीमा की कालावधि नहीं बढ़ा सकता ।"</p> <p>अतः उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में यह निगरानी समय बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है ।</p>	<p> अध्यक्ष</p>